

## प्रदेश में मोबाइल ईसीएचएस शुरू करने की तैयारी

### चर्चा में क्यों?

4 जुलाई, 2023 को उत्तराखण्ड में सैनिक कल्याण विभाग के नदिशक ब्रिगेडियर अमृत लाल ने बताया कि प्रदेश के लगभग दो लाख पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को घर के नज़दीक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने की तैयारी है। इसके लिये पहाड़ में मोबाइल ईसीएचएस (एक्स सर्विसिमेंट कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम) को शुरू करने की तैयारी चल रही है।

### प्रमुख बटु

- पहाड़ों में इस सुविधा से अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे ज़िलों से पलायन रुकेगा।
- वदिति है कि सैन्य बहुल प्रदेश में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुविधा के लिये देहरादून सहित विभिन्न ज़िलों में ईसीएचएस केंद्र बने हैं, लेकिन कुछ केंद्र दूरदराज के क्षेत्रों में होने से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को इसका लाभ नहीं मलि पा रहा है। खासकर वे पूर्व सैनिक केंद्र तक नहीं पहुँच पाते, जिनकी उमर 80 साल या फरि इससे अधिक है।
- ज्ञातव्य है कि सैनिक कल्याण विभाग के नदिशक के अनुसार, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की इस साल अप्रैल में नई दलिली में हुई बैठक में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से इस मसले को उठाया गया था।
- बैठक में बताया गया कि उत्तराखण्ड परवतीय राज्य है, जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग है। ईसीएचएस के लिये मानक एक समान होने से भी प्रदेश में दक्कित पेश आ रही है।
- सेना मुख्यालय की ओर से ईसीएचएस के लिये देशभर में समान मानक तय किये गए हैं। सैनिक कल्याण विभाग के नदिशक के मुताबकि, कम से कम 7,500 पूर्व सैनिकों की आबादी पर एक ईसीएचएस स्थापति कयि जा सकता है, जबकि देहरादून ज़िले में 36,500 पूर्व सैनिक हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में उनके आश्रित हैं।
- ईसीएचएस योजना के तहत भारतीय सेना से सेवानवृत्त सैनिकों और अधिकारियों के सेवानवृत्त होते समय अंशदान के रूप में कुछ फीस जमा कराई जाती है। इसके बाद उनका ईसीएचएस कार्ड बनता है, जिस पर उनको और उनके आश्रितों को जीवनभर मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मलिती है। ईसीएचएस के पैनल के नजि अस्पतालों में भी उन्हें स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है।
- मैदान में 40 से 45 कर्मी. की दूरी कुछ देर में तय की जा सकती है, जबकि पहाड़ में इसके लिये घंटों लगते हैं। इसके अलावा पहाड़ में ट्रांसपोर्ट की भी समस्या है। पूर्व सैनिकों को घर के नज़दीक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मलि, इसके लिये केंद्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक में राज्य के पूर्व सैनिकों की इस समस्या को उठाया गया है।